



बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ग्रामीण उत्तरदाताओं के जागरुकता स्तर का अध्ययन : हरियाणा के चयनित जिलों के संदर्भ

प्रीति, शोधार्थी,

लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक

सारांश

किसी भी देश या समाज का विकास तभी संभव है, जब उसमें प्रत्येक पक्ष का विकास हो। जब समाज का प्रत्येक वर्ग चाहे व पुरुष हो अथवा महिला, समान विकास करेंगे तो ही यह समाज आगे बढ़ पाएगा। हमारे देश में आजादी के 75 साल बाद भी बालिका के प्रति सदियों पुरानी सोच और परम्परा अभी भी मौजूद है। जिस से देश की तरक्की पर बुरा प्रभाव पड़ा है। गिरता लिंगानुपात, लड़कियों का कम या बिल्कुल भी पढ़ा लिखाना होना, जीवन में असमानता का अधिकार एकजटिल समस्या बनी हुई है। भारत सरकार ने इसकी ओर ध्यान देते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुवात की है। जिसका उद्देश्य बेटियों के प्रति सकारत्मक सोच को बढ़ावा देना और उनके अधिकार की रक्षा करना है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का अर्थ है लड़कियों को बचाना और उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षित करना। इस योजना की शुरुआत भारतीय सरकार द्वारा हुई। इस योजना का उद्देश्य भारतीय समाज में लड़कियों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यों की कुशलता को बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के बीच जागरुकता उत्पन्न करती है। प्रस्तुत शोध पत्र में हरियाणा राज्य के तीन जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ग्रामीण उत्तरदाताओं के जागरुकता स्तर का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द :- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंगानुपात, जागरुकता, योजना, ग्रामीण उत्तरदाता।

भूमिका (Introduction) :-

लैंगिक विभेद की अवधारणा पूरे भारतवर्ष में एक समस्या के तौर पर रही है। लैंगिक असमानता के कारण सामाजिक संरचना के संतुलन में विकट समस्या उत्पन्न होती है और जिस समाज में लैंगिक असमानता जितनी अधिक होती है उस समाज का विकास उतना ही पीछे की ओर जाता है। इस तरह यह किसी भी समाज, समुदाय या राष्ट्र के



लिए हानिकारक है। इस समस्या से निपटने के लिए लैंगिक विभेद को समाप्त करना और इसके लिए संवेदनशीलता विकसित करना आवश्यक है। हालांकि हमेशा से ही स्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और अनवरत क्रमिक विकास में उनका योगदान भी रहा है किंतु यह पर्याप्त मात्रा में और गुणात्मक रूप से अपेक्षाकृत उतना क्रियाशील नहीं रहा, जितना आवश्यक है। अतः महिलाओं की समाज में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व लैंगिक विभेद को समाप्त करने के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का शुभारंभ किया गया यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल से देशभर में व्यापक स्तर पर लागू की गई।¹

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना : एक परिचय

इस योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा से शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य बच्चों के लिंग अनुपात में चिंताजनक गिरावट और जीवन-चक्र निरंतरता के साथ महिला सशक्तिकरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना है। परंतु इस चिंताजनक प्रवृत्ति को रोकने और पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित कार्यक्रम अथवा व्यापक समर्थन कार्यनीति नहीं थी। सरकार ने शिशु लिंगानुपात में गिरावट की चुनौती को पहचाना, जो बालिकाओं के प्रति लिंगभेदभाव की सूचक है और जिस पर तत्काल ध्यान देने तथा कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया।² इस अभियान की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अगर समाज के लोग पढ़ी-लिखी बहू लाना चाहते हैं, तो वह अपने घर की बेटियों को शिक्षित करने के लिए कई बार सोचते हैं। इसलिए लोगों को अपनी इस दोहरी मानसिकता को त्यागना होगा। समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्मित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला शिक्षा, सुरक्षा, विकास और सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।³



हरियाणा ने इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि राज्य में लिंगानुपात बेहद संवेदनशील स्तर पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक यह योजना एक सामाजिक योजना है। जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों को जन्म से संबंधित जो रूढ़िवादी धारणा है उसे तोड़ा जाए। मुख्य रूप से महिलाओं को प्रदान किया गया दायम दर्जा समाप्त किया जाए। इसके अतिरिक्त लिंग निर्धारण की रोकथाम, भ्रूण हत्या, बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनका विकास व सबसे महत्वपूर्ण उन्हें शिक्षा प्रदान करना इस अभियान की प्राथमिकता है। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर डाक टिकट जारी करने के साथ ही प्रचार वाहन जन जागरण के लिए रवाना किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। इसके अलावा अन्य लोग समूह जैसे सलमान खान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा को भी एम्बेस्टर बनाया गया। वर्तमान समय में हरियाणा सरकार द्वारा फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को इस अभियान की ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।⁴

मुख्य लक्ष्य

लैंगिक असमानता को समाप्त करना, बेटी के जन्म पर खुशी मनाना और शिक्षा पाने के लिए समक्ष बनाना।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य

- लिंग भेद से पुर्वाग्रसित मनोवृत्ति को समाप्त करना।
- बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की पोषण स्थिति में सुधार करना।
- बालिकाओं के लिए सुरक्षित माहौल को प्रोत्साहित करना।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 161 जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामों से उत्साहित होकर और समस्या के आकार और गंभीरता को देखते हुए देशभर में इसका



प्रसार करने के लिए यह महसूस किया गया कि अगर शिशु लिंग अनुपात में समस्त सुधार लाना है तो कोई जिला ऐसा नहीं बचना चाहिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के दायरे में आता हो।⁵

साहित्य समीक्षा

यादव (2012)⁶ "राजस्थान में हरियाणा में उपेक्षित ग्रामीण महिलाएं", प्रस्तुत शोधपत्र में देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद राजस्थान व हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। भारत में विकास के नए प्रतिमान विकसित हुए हैं उदारीकरण के बाद से ही। हरियाणा राज्य लिंगानुपात में सबसे नीचे है और राजस्थान में महिला साक्षरता सबसे निचले पायदान पर आ गया है। ग्रामीण महिलाओं की दयनीय स्थिति बनी रहना इन विकास के रास्तों पर कालिख के समान है। आजादी के छः दशक बाद भी ग्रामीण राजस्थान में आधी से अधिक आबादी निरक्षर है।

टंडन एवं शर्मा (2016)⁷ "फीमेल फीटिसाइड इन इंडिया: एन एनालिसिस ऑफ क्राइम्स", प्रस्तुत लेख कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या से संबंधित सभी धारणों जैसे लिंग आधारित गर्भपात कानूनी पहलू, नीतिगत ढांचा आदि को समाहित करने का प्रयास करते हैं। इसके अन्दर प्रत्येक राज्य के कन्या शिशु अपराध का विश्लेषण किया गया है। अतः में जागरूकता अभियान लोग अपील तथा सामाजिक बदलाव लाने पर जोर दिया गया है।

कौशिक (2019)⁸ "महिलाओं संबंधी योजनाओं में हरियाणा", ने अपने लेख में बताया गया है कि जब हम हरियाणा में महिलाओं संबंधी कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं तो देखते हैं कि हरियाणा में नारी के कल्याण के लिए हर क्षेत्र में भरपूर प्रयास किए हैं, चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का सशक्तिकरण का हो या जागरूक करने का अथवा पुरुष महिला लिंगानुपात में सुधार करने का, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में कटिबद्ध नजर आ रही है।



शोध उद्देश्य :-

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति ग्रामीण उत्तरदाताओं के जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।

शोध का समग्र

प्रस्तुत शोध में हरियाणा राज्य के सिरसा, महेंद्रगढ़ व रोहतक का चयन किया गया है।

प्रतिदर्शन का चयन

शोध के लिए सिरसा, महेंद्रगढ़ व रोहतक से 420 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि (Purposive Sampling Method) द्वारा किया गया है।

प्रतिदर्शन का वर्गीकरण

क्र० सं०	जिला	उत्तरदाताओं की संख्या
1.	सिरसा, महेंद्रगढ़ व रोहतक	105 गर्भवती महिला, 105 स्तनपान वाली महिला, 105 नवविवाहित जोड़े, 105 बेटी संतान के अभिभावक कुल 420 उत्तरदाता

आंकड़ों का संकलन तथा एकत्रीकरण

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का संकलन किया गया है।

प्राथमिक आंकड़े : प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण, ग्रामीण उत्तरदाताओं द्वारा अनुसूची विधि से किया गया है।

द्वितीयक आंकड़े : द्वितीयक आंकड़ों का संकलन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, का वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक



रिपोर्ट, समाचार पत्र, पत्रिका, प्रकाशित व अप्रकाशित शोध ग्रंथ, मीडिया व इंटरनेट के माध्यम से किया गया है।

सारणीयन एव मूल्यांकन

प्राथमिक विधि से संकलित आंकड़ों का सारणीयन व मूल्यांकन किया गया है तथा शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित सुझाव प्रदान किए गए हैं।

आंकड़ों का विश्लेषण (Data Analysis) :-

संपूर्ण कार्य के उपरान्त विश्लेषण के लिए अनुपात (Ratio) या प्रतिशत का प्रयोग किया गया है।

परिणाम एवं निष्कर्ष :-

सारणी-1.1

क्या आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विषय में जानते हैं।

क्र० सं०	जिला	हाँ	नहीं	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1.	सिरसा	180 (100%)	0	180 (100%)
2.	महेन्द्रगढ़	120 (100%)	0	120 (100%)
3.	रोहतक	120 (100%)	0	120 (100%)
4.	कुल	420 (100%)	0	420 (100%)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित।



उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि तीनों जिलों सिरसा, महेन्द्रगढ़ व रोहतक में 100 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी है। जिसका प्रमुख कारण यह है कि स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को इस योजना के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस योजना के साथ जोड़ा जा सके तथा सरकार की यह एक मात्र ऐसी योजना है, जिसके विषय के अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक इस योजना की जानकारी है। सबको यह भी पता है कि यह योजना लड़कियों के लिए चलाई जा रही है।

सारणी-1.2

आपकी जानकारी का स्रोत क्या है।

क्र० सं०	जिला	मीडिया	सरपंच	आंगनवाड़ी वर्कर	एएनएम आशा वर्कर	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1.	सिरसा	16 (8.9)	4 (2.2)	46 (25.6)	114 (63.3)	180 (100)
2.	महेन्द्रगढ़	19 (15.8)	16 (13.3)	24 (20.0)	61 (50.8)	120 (100)
3.	रोहतक	7 (5.8)	1 (0.8)	40 (33.3)	72 (60.0)	120 (100)
4.	कुल	42 (10.0)	21 (5.0)	110 (26.2)	247 (58.8)	420 (100)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित।

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिला सिरसा के 63.3 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं का ये कहना है कि उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी एएनएम/आशा वर्करों द्वारा प्राप्त हुई तथा 25.6 प्रतिशत की जानकारी का स्रोत आंगनवाड़ी वर्कर व 8.9 प्रतिशत की मीडिया और 2.2 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं का ये कहना है कि उन्हें मीडिया व सरपंचों के द्वारा इस योजना की जानकारी प्राप्त हुई है इसी सन्दर्भ में जिला महेन्द्रगढ़ के 50.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं की जानकारी का स्रोत एएनएम व आशा वर्कर है जबकि 20.0 प्रतिशत की आंगनवाड़ी 15.8 प्रतिशत की मीडिया व 13.3 प्रतिशत की जानकारी का स्रोत सरपंच है जिन्होंने इस योजना के सम्बन्ध में लोगों को बताया है। इसी प्रकार से जिला रोहतक के 60.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं की जानकारी का



स्रोत एएनएम/आशा वर्कर और 33.3 प्रतिशत आंगनवाड़ी वर्कर तथा 5.8 प्रतिशत की मीडिया व 0.8 प्रतिशत की जानकारी का स्रोत सरपंच है। इसी सन्दर्भ में यदि तीनों जिलों की स्थिति का अध्ययन करे तो 58.8 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं का ये कहना है कि उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी एएनएम व आशा वर्करों द्वारा प्राप्त हुई है क्योंकि ये जब भी घर आती या हम स्वास्थ्य केन्द्र पर जांच के लिए जाते थे तो ये वर्कर हमें इस योजना के विषय में बताते थे और 26.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ये कहना है कि उन्हें आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा इस योजना के विषय में पता चला है तथा आंगनवाड़ी वर्कर भी घर-घर आती थी। इस योजना के विषय में बताने व बैठके आयोजित करवाती थी जबकि 10.0 प्रतिशत को मीडिया के माध्यम से जैसे कि अखबार व टी०वी० इत्यादि द्वारा इनको पता चला है और 5.0 प्रतिशत को सरपंचो के माध्यम से इस योजना की जानकारी पता चली है। स्थानीय स्तर पर जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वह भी सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाने में मदद करते हैं।

सारणी-1.3

क्या आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रावधानों के बारे में पूर्ण जानकारी है

क्र० सं०	जिला	हाँ	नहीं	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1.	सिरसा	180 (100:)	0	180 (100:)
2.	महेन्द्रगढ़	120 (100:)	0	120 (100:)
3.	रोहतक	120 (100:)	0	120 (100:)
4.	कुल	420 (100:)	0	420 (100:)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित।



उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि तीनों जिलों सिरसा, महेन्द्रगढ़ व रोहतक में 100 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं को बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना के प्रावधानों की पूर्ण जानकारी है क्योंकि लगभग सभी उत्तरदाता शिक्षित हैं और अखबार पढ़ते हैं तथा वे सभी टीवी भी देखते हैं इसके साथ ही ये सभी स्थानीय स्तर पर नियुक्त आंगनवाड़ी, आशा वर्कर व एएनएम से इस योजना के प्रावधानों के विषय में पूछते रहते हैं तथा जब भी कोई महिला गर्भवती होती है या किसी के घर बच्चा पैदा होता या फिर जिस भी किसी बच्चे का विवाह होता है तो उन सब की जानकारी ये अपने रजिस्टर में लिखती तथा साथ ही साथ बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना के विषय में भी बताती है ताकि अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे लोग भी इस योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकें और स्थानीय स्तर पर इस योजना को क्रियान्वित करने इसके प्रावधानों के सम्बन्ध में लोगों को अवगत कराना इन सभी कार्यकर्ताओं की ही अहम जिम्मेवारी होती है।

निष्कर्ष व सुझाव

बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना ने बेटियों पर बेटों को तरजीह देने की बड़ी समस्या को सामने लाने में बड़ी कामयाबी जरूर हासिल की है। लेकिन अपने मौजूदा स्वरूप में इस योजना के अपना मुख्य मकसद हासिल करने में नाकाम होने की आशंका है क्योंकि इसे लागू करने और निगरानी में काफी कमियां हैं। जिला और राज्य स्तर पर नियमित रूप से बैठकों की कमी के चलते इस योजना ने पिछले कुछ वर्षों में जो माहौल बनाया है, उससे पीछे हो जाने का डर है। ऐसे में ये जरूरी है कि राज्य और जिला स्तर पर योजना को लागू करने वाली समितियों में सामुदायिक स्तर के कर्मचारियों की नुमाइंदगी बढ़े। इस योजना को लागू करके जो लक्ष्य हासिल किए जाने हैं, उन सूचकांकों में सुधार लाना है, तो इस योजना के तहत उन चुनौतियों को भी समझना और दूर करना होगा। जो पढ़ने वाली लड़कियों को झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि शौचालय का न होना। इसके अलावा इस योजना की नियमित निगरानी और मूल्यांकन की भी मजबूत व्यवस्था बनानी होगी।

- ✓ स्थानीय स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों व कार्यकर्ताओं को बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना का प्रचार-प्रसार जोर-जोर से करना चाहिए।



- ✓ सभी जिलों में सर्वप्रथम जहाँ पर जिस किसी जगह का लिंगानुपात निम्न है वहाँ पर आशा, ए.एन.एम. व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के महत्व के सम्बन्ध में जानकारी दी जानी चाहिए।
- ✓ तीनों जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए व नवविवाहित जोड़ों को भी इस योजना की जानकारी गाँव व शहर के अन्दर विस्तारपूर्वक समझाई जाए।
- ✓ सभी जिलों में सरकार द्वारा बेटियों के जन्म पर प्रत्येक बेटी के बैंक खाते में उचित धनराशि दी जानी चाहिए ताकि कोई भी माता-पिता बेटी को बोझ न समझे।
- ✓ तीनों जिलों में जहाँ कहीं भी कन्या भ्रूण हत्या होती है या जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करवाते हैं, उनको उचित दंड दिया जाए ताकि और लोग भी ऐसी घिनौनी हरकत ना कर पाए।
- ✓ तीनों जिलों में सरकार द्वारा बाल-विवाह को रोकने के लिए गाँव स्तर पर पंचायतों के साथ मिलकर कमेटियां बनाई जानी चाहिए ताकि बाल-विवाह को रोका जा सके। साथ ही गाँव व शहर के प्रत्येक मोहल्लों में बाल-विवाह के दुष्परिणामों के सम्बन्ध में समय-समय पर जागरूकता कैम्पों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- ✓ सभी जिलों में सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए साथ ही ग्रामीण स्तर पर लोगों को बेटियों की शिक्षा के प्रति भी जागरूक किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

- चंद्र, गिरीश पांडे (2015), "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना", प्रतियोगिता दर्पण, सामाजिक लेख, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 96
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में- एक परिचय, नई दिल्ली, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2015 भारत सरकार
- वर्मा मनीषा, उपरोक्त वही, पृष्ठ संख्या 42



-
- एनडीए सरकार की योजनाएं: एक सिंहावलोकन, प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, 2016 पृष्ठ संख्या 158
 - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में एक परिचय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 2015 भारत सरकार
 - यादव विकास (2012), "राजस्थान व हरियाणा में उपेक्षित ग्रामीण महिलाएं", सूचना और प्रसारण, नई दिल्ली
 - लता टंडन स्नेह एवं शर्मा रेनू (2016), "फीमेल फीटिसाइड एंड इनफीटिसाइड इन इंडिया: एनालिसिस ऑफ क्राइम्स", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस साइंस, वॉल्यूम 1, अंक 1
 - कौशिक जगबीर (2019) "महिलाओं संबंधी योजनाओं में परिप्रेक्ष्य में हरियाणा", कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली